(b) Targets for 1992-93 :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Certified Seed . . | 476000 |
| (ii) | Foundation Seed . . | 35366 |
| (iii) | Breeder Seed . . | Nil |

**Share of Ravi -Bass Waters for Haryana**

H79L SHRI & S. SURJEWALA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the share in the Ravi-Beas waters which have been allocated to Haryana by the Erady Tribunal and the quantum of water already being used by Haryana;

(b) the hectare of land that could have been irrogatedin Haryana had the entire share of water flowed in the State from the date of decision of Erady Tribual;

(c) the loss which the farmers in Haryan* State suffered) on account of non-reCefpt of this water and whether Government would consider *to* re-imburse this loss to Hie farmers; and

(4) by which date the Sutlej-Yamuna Link canal in Punjab territory, is likely to be constructed and entire share of Haryana in the Sutlej-Yamuna Link water start

*THE* MINISTER. OF WATER RE-S0MICES (SHRI V. C SHUKLA!) : (a) A#per the "Report of the Ravi-Beas Waters T#pnal" of January 1987 Haryana has htm allocated 4.72 Billion Cubic Metres of Surplus Ravi-Bens waters. The Tribunal haw also assessed the quantum of water used by the fanners and other consumptive us*?s in Haryana as on 1-7-85 as 2.00 Billion metres.

(b.)i and (c) Does not arise as decisions of the Tribunal shall become effective only after receipt of its further report giving explanation and guidance on the points made out by the states and the Government of India under Section 5(3) and after the decisions of the Tribunal are published in

(dl Time schedule for completing the SYL Canal will depend upon nature and capacity of the new agency/agencies to be engaged by the Government of Punjab.

**नई इस्पात नीति**

*150. श्री राम जेठमलानी :

श्री वीरेन जे० शाह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई इस्पात नीति की घोषणा होने के पश्चात्, सरकार ने नई उदार नीति के प्रभावों का अध्ययन करने और व्यापार के विकास हेतु सुझाव देने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है,

(ग) समिति ने इस संबंध में क्या-क्या सुझाव दिये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) नई उदार नीति के प्रभावों का अध्ययन करने तथा व्यापार के विकास हेतु सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने हेतु एक कृत्यक बल का गठन किया है।

(ख) से (ङ) कृत्यक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार जांच कर रही है। कृत्यक बल की सिफारिशों तथा उन पर की गयी कार्रवाई के ब्यौरे का पता जांच के बाद ही लगेगा।